(b) whether the said Bill would be introduced in the current session of Parliament?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) and (b). This had to be first considered by Screening Committee and since then changes in Government during the last one year, have necessitated some time to finalise a decision. A decision on the proposal to nationalise the Company is expected to be taken soon.

Soviet Union's offer to augment Coal Production

1786. **SHRIMATI GEETA MUKHERJEE**: Will the Minister of ENERGY AND COAL be pleased to state:

(a) whether the Soviet Union has offered its help in augmentation of coal production; and

(b) if so, the details and what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) Yes, Sir.

(b) The Coal India Limited have entered into a number of contracts with USSR for new underground mining technology, design of large opencast mine projects and washeries, modernisation of coal washeries and mine construction.

राज्य बिजली बोर्डों में उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि

1787. **श्री कुम्भा राम आर्य**: क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बिजली बोर्डों में प्रतिनिधि उपभोक्ताओं की श्रेणियों के आधार पर लिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य बिजली बोर्डों में कृषक श्रेणी से (जो बिजली का उपयोग करते हैं) सदस्यों की संख्या और उनके नाम क्या हैं; और

(ग) यदि ऐसे सदस्य किसी भी राज्य में नहीं हैं तो उसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): (क) से (ग). राज्य बिजली बोर्डों में प्रतिनिधि उपभोक्ताओं की श्रेणियों के आधार पर नहीं लिए जाते। अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति जिनसे राज्य बिजली बोर्डों का गठन होता है। वाणिज्यिक मामलों तथा प्रशासन में अनुभव के आधार पर तथा पब्लिक युटिलिटी उपक्रमों में, अधिमान्यत: किसी विद्युत प्रदाय संस्थान में विद्युत इन्जीनियरी, लेखा और वित्तीय मामलों के क्षेत्र में उनकी योग्यता तथा अनुभव के आधार पर राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

तथापि, राज्य बिजली परामर्शदात्री परिषद के गठन के लिए प्रावधान जिसमें अन्य श्रेणियों के साथ-साथ स्थानीय स्वायत्त शासन, विद्युत सप्लाई उद्योग, वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि जैसी विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि भी संबधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसमें यह भी प्रावधान है कि परिषद में ऐसे प्रत्येक हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम एक सदस्य होगा। राज्य बिजली परामर्शदात्री परिषद का मुख्य कार्य राज्य बिजली बोर्ड की नीति-निर्धारण तथा बड़ी स्कीमों संबंधी प्रमुख मामलों में सलाह देना है।

Tata's Proposal to set up Thermal Power Plant at Trombay

1788. **SHRI CHHITUBHAI GAMIT**: Will the Minister of ENERGY AND COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Tatas have made proposal to Government to set up a second 500 MW thermal power plant at Trombay; and

(b) if so, what are its details?